मेरे खाने में कीटनाशक?

जी नहीं, धन्यवाद !

रोज एक सेव का सेवन कर आप अपने स्वास्थ्य को खटाई में डाल सकते हैं। जी हाँ, आपने सही पढ़ा ! सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि प्रतिबंधित कीटनाशक जैसे कलोरडेन, हेप्टाक्लोर और डी डी टी हमारे भोजन में मौजूद हैं।

कलोरडेन की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम को क्षति पहुँचती है। इतना हीं नहीं इससे फेफड़ों, गुर्दे, और किडनी के साथ हीं आँखों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल किसी फसल के उत्पादन में नहीं होना चाहिए, उनके अंश भी भोजन में मिल रहे हैं।

कानून के अनुसार, मोनोक्रोटोफौस जिसे उसके तीव्र (एक्यूट) और दीर्घकालीन (क्रोनिक) प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के लिए जाना जाता है, यह भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों में से एक है। हालाँकि, भारत में कई एजेंसियां अपने शोध में सब्जियों में मौजूद जहरीले पदार्थों में मोनोक्रोटोफौस की उपस्थिति के आंकड़े प्रस्तुत कर चुकी हैं। जिन कीटनाशकों/ जहरीले पदार्थों की खेतों में इस्तेमाल करने की अनुमति है, उनके अंश भी भोजन में कानूनी अनुमति की सीमा से बहुत ज्यादा पाए गये हैं।इसके पर्याप्त उदाहरण हैं कि भारत में किस तरह हमारा भोजन, पानी और मिट्टी रासायनिक कीटनाशकों की वजह से प्रदूषित हो रहे हैं।

आप अपने प्रयासों के बारे में जरा सोचिए जिससे आप यह सुनिश्चित करते हैं कि सुपरमार्केट, स्थानीय बाज़ार या छोटे विक्रेता से ख़रीदे गये सब्जी या फल ताजे हों, आप उन्हें पानी से धोते हैं, साफ़ करते हैं, काटते हैं, पकाते हैं,और फिर अपने प्रियजनों को खिलते हैं या खुद खाते हैं .आप इतने प्रयास सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनमें मौजूदा जहरीले पदार्थ धीरे धीरे चले जाएँ। परन्तु क्या आप साफ़ सुथरा भोजन कर पाते हैं? वास्तव में फल, सब्जियां, मांस, पौल्ट्री और दूध में बहुत ज्यादे मात्रा में कीटनाशक होते हैं। कई मर्तबा तो यह भारतीय कानूनों में तय अधिकतम शेष सीमा (एम आर एल) से बहुत ज्यादे होते हैं। इतना हीं नहीं, हमारा पेय जल भी प्रदूषित हो चुका है ! सबसे विषम स्थिति तो यह है कि माँ का दूध भी जहरीला हो चला है !!!

पूरे देश को जहर देने की प्रक्रिया की निगरानी या इसे रोकने के लिए कठोर करवाई कोई नहीं कर रहा है!

सरकार अनदेखी कर रही है

यह साबित हो चुका है कि सारी समस्या की जड़ हमारे खेतों में है । यहाँ भारत सरकार का इन खतरनाक रसायनों के प्रति समर्थन जारी है । इन समस्याओं की जानकारी होने और रासायनिक कीटनाशकों के पर्याप्त विकल्प होने के बावजूद सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है । कीटनाशक उद्योग को खुशहाल बनाये रखने के लिए नागरिकों की सेहत के साथ खुलेआम समझौता हो रहा है । स्थिति को और बुरा बनाने के लिए सरकार जेनेटिकली मोडीफाएड (जी एम) फसलों को प्रोत्साहन देकर समाधान के रूप में उन्हें प्रस्तुत कर रही है. जो खतरनाक और हानिकारक है । इसके परिणाम भी अपरिवर्तनीय हैं ।

इसके स्थान पर सरकार को सुरक्षित विकल्पों को समर्थन देना चाहिए। जबकि सरकार तो उनके लिए उचित प्रतिस्पर्धात्मक महल भी उपलब्ध नहीं करा रही। इस समय हमारे अन्नदाता, किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है। हकीकत है कि फसल की बढ़ती लागत, कर्ज और कीटनाशकों व अन्य सम्बंधित मामलों की वजह से स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ गयी हैं। इससे किसान गहरे संकट में हैं।

इसके बावजूद भी खुशखबरी है

खुशखबरी यह है कि दुनिया भर में खेती के सुरक्षित विकल्पों को लेकर प्रयोग हो रहे हैं। उसके फायदे सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए आँध्रप्रदेश में लाखों किसानों ने गैर-कीटनाशक प्रबंधन (एन पी एम) की खेती को अपनाया। रिपोर्ट बताती है कि किसानों को यह खेती ज्यादा लाभदायक नजर आती है। यदि खाद्य उत्पादन में किसी तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया गया तो हमारे भोजन में भी कीटनाशक के अंश नहीं मिलेंगे।

भारत सरकार बुराईयों को छोड़ने में हिचकिचाहट दिखा रही है। इतना ही नहीं उसने तो कीटनाशक उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति हीं बना ली है। ऐसे में हम उपभोक्ताओं को एक होकर सुरक्षित भोजन की मांग करनी होगी। एक नागरिक होने के नाते सुरक्षित भोजन पाने का हमें पूर्ण अधिकार है

।आप बन सकते हैं बदलाव के एजेंट-

ऐसे जहर का सेवन करने के लिए हम विवश किये जा चुके हैं। समय आ गया है कि चुनौती की इस घड़ी में एक नागरिक के हैसियत से सरकार से हम माँग करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण को उचित तबज्जो, तरजीह दी जाये ।सरकार के लिए बड़ी कंपनियों के मुनाफे हीं मायने नहीं रखने चाहिए ।खतरनाक रसायनों को सरकार खाए तो खाए, हम नागरिकों को ना खिलाये।

हम सरकार से माँग करते हैं कि :

- जैविक/ पर्यावरणीय/ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और प्रोत्साहन दें, जिसमे कीटनाशकों और जेनेटिक मोडीफाएड (जैव परिवर्धित) प्रणाली शामिल न हो।
- जैविक भोजन सुनिश्चित करें खाश तौर पर गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं तथा हमारे नन्हे मुन्नों को।
- उन कीटनाशकों पर प्रतिबन्ध लगाये जाएँ जिन पर अन्य देशो में प्रतिबंध लगा हुआ है।

लॉग ऑन करें: **www.indiaforsafefood.in, और पेटीशन (याचिका) पर हस्ताक्षर करें।**

हम इस मसले को केंद्रीय कृषि मंत्री के समक्ष उठाएंगे। वेवसाईट आपको यह भी बताएगी कि आप इस बदलाव में कैसे शामिल हो सकते हैं।

इसके लिए क्या कर सकते हैं?

इस नम्बर पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल दीजिए:

022-33010031

India for Safe Food

Safe Food - Our Right! No Chemicals, No GM!